यूनविर्सल बेसकि इनकमः आर्थकि-सामाजकि सुरक्षा की ओर बढ़ते कदम

क्या है यूबीआई?

- यूबीआई एक न्यूनतम आधारभूत आय की गारंटी है, जो प्रत्येक नागरकि को बनिा कसिी न्यूनतम अर्हता के आजीवकिा के लयि हर माह सरकार द्वारा दी जाएगी।
- यह बेशर्तयि और सर्वजनीन अधकिार है, तथा इसके लयि व्यक्तकिो केवल भारत का नागरकि होना ज़रूरी होगा।
- यह व्यक्तकिो कसिी अन्य स्त्रोत से हो रही आय के अलावा प्राप्त होगी।

यूबीआई की पृष्ठभूम

- हाल ही में यूबीआई की अवधारणा को लागू करने के संदर्भ में स्वट्जिरलैंड पहला ऐसा देश है, जसिने पछिले साल इस पर जनमत संग्रह कयि। परन्तु यूबीआई के वत्तिीय प्रभाव और इसकी वजह से लोगों में काम करने की प्रेरणा के खत्म होने की आशंका से स्वट्जिरलैंड की जनता ने इसे खारजि कर दयि।
- वर्तमान में फनिलैंड ने यूबीआई को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू कयि है, जसिके तहत बहुत थोड़े से लोगों को हर महीने 595 डॉलर के बराबर की राशदिी जाएगी।
- हाल में भारत में यह अवधारणा चर्चा में इसलयि आई क्योंकि 2016-17 के भारत के आर्थकि सर्वेक्षण में यूबीआई को एक अध्याय के रूप में शमलि कर इसके ववििधि पक्षों पर चर्चा की गई है।

यूबीआई के पक्ष में तर्क

- प्रत्येक व्यक्तकिो एक न्यूनतम आय की गांरटी प्रदान करने का यह वचिार, नश्चिति तौर पर संवधिान द्वारा नागरकिों को प्रदान कए गए गरमिामय जीवन जीने के अधकिार को वास्तवकिता प्रदान करेगा।
- सरकार द्वारा नयित राशदियि जाने से गरीबी और गरीबी के कगार पर खड़े लोग उपभोग के एक नश्चिति स्तर को प्राप्त कर सकेंगे और इस तरह वे अपनी आर्थकि दशा सुधारने में सक्षम हो सकेंगे।
- भारतीय अर्थव्यवस्था में जहाँ असंगठति क्षेत्र में 90% कामगार हों, बहुत से लोग नःिशक्त व भक्षिावृत्तसि जुड़े हों, देश के कई भागों में लोग हर वर्ष प्राकृतकि आपदा से त्रस्त हों एवं वभिन्नि प्रकार की अनयिोजति वकिासात्मक गतविधिि के कारण पलायन को मजबूर हों, उन्हें आर्थकि असुरक्षा के भय से मुक्तमिलिेगी।
- कल्याणकारी व्यय के उपयोग की जम्मिेदारी अब नागरकिों पर भी होगी एवं लेटलतीफी, अफसरशाही, लाभों के मनमाने वतिरण आदकिी समस्याओं से मुक्तमिलिेगी।

यूबीआई के संभावति लाभ

- यूबीआई का सबसे बड़ा लाभ है इसका यूनविर्सल या सर्वजनीन होना, अर्थात् कसिी वर्ग वशिेष को या कसिी जरूरतमंद वर्ग समूह को अलग से चह्निति या लक्षति न करके सभी को एक न्यूनतम धनराशउिपलब्ध कराना।
- साथ ही मौसमी व प्रच्छन्न बेरोज़गारी, आपदा, रोगावस्था, नःिशक्तता एवं नयिोक्ता द्वारा शोषण की अवस्था में व्यक्तरिोज़गार के अभाव में भी अपना जीवनयापन कर सकेगा।
- प्रणाली क्षरण (system leakage) की समस्या कम होगी एवं जैम प्रणाली (जनधन, आधार, मोबाइल) के उपयोग से लाभार्थी तक सीधे पहुँचा जा सकेगा।
- धन के आवंटन, नगिरानी व भ्रष्टाचार पर अंकुश के अनावश्यक दायत्वि से नौकरशाही मुक्त होगी, जसिसे वकिास के अन्य कार्यों को गतमिलिेगी।

यूबीआई के वपिक्ष में तर्क

- एक सतत् सर्वजनीन बुनयिादी आय लोगों में कार्य करने के प्रोत्साहन को कम कर सकती है।
- हमारे पतिृसत्तात्मक समाज में सरकार द्वारा महलिाओं को जो बुनयिादी आय प्रदान की जाएगी, उस पर संभव है कपिुरूषों का नयिंत्रण हो जाए।
- यूबीआई से मजदूरी की दर बढ़ने से, वस्तुओं व सेवाओं की मूल्य वृद्धसि महँगाई का ऊर्ध्वाधर चक्र शुरू हो जाएगा।
- बेसकि आय के स्तर को उच्च बनाए रखने में भारत का राजकोषीय संतुलन प्रभावति होगा।

यूबीआई से जुड़े अनुत्तरित प्रश्न

- क्या यूबीआई जनकल्याण की अन्य दूसरी योजनाओं को विदा कर देगी? यदि हाँ तो सरकारी सहायता के अभाव और मांग में वृद्धि से उत्पन्न महँगाई को बेसिक आय कैसे संतुलित कर पाएगी?
- सबसे जटिल प्रश्न यह है कि बेसिक आय का 'मान' क्या होगा? यदि गरीबी रेखा हो तो ग्रामीण क्षेत्र में 32रुपए एवं शहरी क्षेत्र में औसतन 40 रुपए के अनुसार लगभग 1200 प्रतिमाह व वर्ष के 19,400 रुपए होंगे। क्या इससे व्यक्ति अपनी अवश्यकताओं को पूरा कर पाएगा?
- फिर इस योजना के लिये सरकार पर जो बोझ होगा, वह भारतीय GDP का 9 से 10 फीसदी तक होगा। वह कहाँ से आएगा?

निष्कर्ष

- यूबीआई निश्चित तौर पर सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा के संबंध में एक आकर्षक विचार है। किन्तु इसका खाका व्यावहारिक आधारों पर होना चाहिये, ताकि वित्तीय बोझ व राजकोषीय असंतुलन का खतरा न रहे।

इस योजना से धनी व उच्च मध्यमवर्गीय लाभार्थियों को बाहर किया जाना चाहिये। निर्धन ब्लॉक एवं जिलों में 'पायलट प्रोजेक्ट' के तौर पर लागू कर इसका बारीकी से मूल्यांकन करना चाहिए। इसके बाद ही चरणबद्ध तरीके से इस योजना को पूरे भारत में लागू करना चाहिये।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/universal-basic-income-1